जोधपुर शहर का औद्योगिक विकास, शहर का एतिहासिक महत्व है और धार्मिक व पर्यटन क; दृष्टि से बढ़ते महत्व को देखते हुए अस्थायी आने वालों की जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है।

अत: वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर जोधपुर शहर को अविलम्ब बी–2 श्रेणी का शहर घोषित कर केन्द्रीय कर्मचारियों एवं आम जनता को न्याय दें।

(iv) Need to set up small scale and other industries in Punia district of Bihar.

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान बिहार के पूर्णिया क्षेत्र की गंभीर समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगी जहां पर बेकारी के कारण लोग इधर उधर भटक रहे हैं। एक तो यह पिछड़ा क्षेत्र है ही, दूसरे सरकार के ध्यान नहीं देने के कारण इसकी स्थिति और भी बदतर होती जा रही है।

सरकार ने दो जूट मिलों को खोलने का विचार किया है, अत: सरकार से अनुरोध है कि दोनों मिलों को विभिन्न स्थानों पर खोले, ताकि पूरे क्षेत्र के लोग समान रूप से फायदा ले सकें।

मैं उद्योग मंत्री जी से गुजारिश करना चाहूंगी कि इस क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए तत्काल लघु उद्योग धंधों को स्थापित करायें। विशेषज्ञों की एक समिति भेजकर स्थिति का जायजा लेकर उपयुक्त लघु उद्योग धंधों का काम शुरू करायें, ताकि मति भ्रमित एवं चिन्तित नवयुवक पथभ्रष्ट होने से बचाए जा सकें। इस क्षेत्र में पटसन की भी अधिकता है। अत: कटाई एवं टाट-बोरा उद्योग, दरी एवं धागों से बने अन्य छोटे–छोटे उद्योगों को पनपा कर विकास की पूर्णता की जाये। साथ ही खादी उद्योग डेरी-फार्म लघु चर्म उद्योग आदि के लिये बेहतर भूमिका प्रदान की जाए। और सरकार राज्य सरकार को भी निर्देश दे कि इस क्षेत्र की बिगड़ती स्थिति को सुधारने हेतु विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि जन-जीवन सुखमय हो सके। इस क्षेत्र की जनता का जीवन-स्तर ऊंचा नहीं तो सामान्य तो हो सके। यहां पर लघु उद्योग धंधों के विकास की पूर्ण सुविधायें उपलब्ध हैं। लघु उद्योगों में अधिक पूंजी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लोगों को काम मिल सकेगा, यही नहीं पटसन से बनी वस्तुओं से तो विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति हो सकेगी। अत : इस ओर सरकार अपेक्षित कदम उठाये और इस तिमिरावृत्त क्षेत्र में प्रकाश की एक किरण तो अवश्य ही पहुंचायें।

(v) Problems of Extravt departmental employees of P & T department.

श्री राम लाल राही : (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन आप के माध्यम से अविलम्बनीय लोकमहत्व के निम्नलिखित विषय को उठाना चाहता हूं—

संचार सुविधा जनता के लिये दिनों–दिन दुरूह व दूभर होती जा रही है। इस के विकास में जिस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई लग रही है उस के अनुरूप विभाग देश की जनता को सुविधा दिलाने में असफल रहा है। नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में हर 5 से 8 किलोमीटर की दूरी पर उप-डाकघर खोले जा रहे हैं। यही नहीं जनसुविधाओं हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 किलोमीटर के मध्य अब पी० सी० ओ० की भी सुविधा की गई है परन्तु 90 प्रतिशत पी०सी०ओ० महीनों से ग्रामीण क्षेत्रों में खराब हालत में पड़े हैं। कोई देखने वाला नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में उप-डाकघर खोलने का आधार यदि अल्प बचत योजना को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया होता और उपडाकघरों में लगे लोगों को वाजिब वेतन व सुविधायें दे कर उन से अल्प

[श्री राम लाल राही]

बचत के महत्वपूर्ण कार्य की तरफ लगाया होता तो संचार विभाग से ग्रामीण स्तर तक के आम आदमी को लाभ दृष्टिगोचर होता और सर्वहारी वर्ग के लोग महाजनी कुवृत्ति से मुक्ति पाने के लिये रास्ता पाते। पर प्रौढ़ शिक्षा के ही समान लगता है पोस्ट आफिस खोलने का उद्देश्य गौण होता जा रहा है और स्वार्थ की अभिव्यक्ति होती है। संचार व्यवस्था में लगे अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी शोषण, अन्याय और उत्पीड़न के शिकार हैं। सुविधाओं के नाम पर ड्यूटी करते समय मर जाने पर भी सरकार की तरफ से इन्हें वैधानिक या मानवीय रूप से किसी भी प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई है और न इन के परिवार के राहत की व्यवस्था। लंबी अवधि तक कार्य करने के बाद भी कोई कर्मचारी न तो रेगुलराइज हो पाता है न स्थायी, न पदोन्नति के अवसर उन के लिये उपलब्ध होते हैं। डाक सुरक्षा के लिये वे भीगते हुए थैला ले कर क्यों न जांय, उन के लिये अन्य कर्मचारियों की तरह छाते तक की व्यवस्था नहीं है। न ही चिकित्सा की कोई सुविधा है, न आवासीय, जब कि समान काम के लिये समान वेतन के सिद्धांत के आधार पर इन्हें भी पूर्णकालिक विभागीय कर्मचारी मान कर समस्त सुविधायें दी जानी चाहिये। मेरी सरकार से मांग है कि अल्प बचत योजना से समस्त ग्रामीण क्षेत्रीय सब पोस्ट आफिस के कर्मियों को युद्ध स्तर पर लगाना चाहिये ताकि साधारण किसानों, श्रमिकों, खेतिहर मजदूरों, ग्रामीण शिल्पकारों, को अल्प बचत के लिये प्रेरणा मिले, बचत कर अपने परिवार के पालन-पोषण व राष्ट्रीय निर्माण में भागीदार बनें, महाजनी संकट से छुटकारा पावें, तथा अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को विभागीय कर्मचारी घोषित कर उन्हें रेगुलराइज किया जाये, पदोन्नति के अवसर दिये जायं तथा अन्य डाक विभाग कर्मचारियों के समान चिकित्सा स्वास्थ्य, वस्त्रों आदि की सुविधायें दी जायं।

(vi) NEED FOR NATIONALISATION OF M/s MOTOR AND MACHINERY MANUFACTURERS, LTD. CALCUTTA

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur): Sir, Motor and Machinery Manufacturers Limited was taken over by the Central Government on 9-10-1974. Since then the industry has been making remarkable progress in the matter of production of Motors and allied machineries. Motor and Machinery Manufacturers Ltd. Workers Union (CITU) and several Members of Parliament have drawn the attention of the Government of the urgent need for immediate nationalisation or amalagamation of the said unit with BHEL or some such big public sector industry.

Sir, in the month of January last a technical study team of BHEL visited the industry and reported to have submitted a favourable report to the Industry Ministry after its revival scheme has been successfully implemented by this unit due to the sincere cooperation between the workers and the management.

Sir, it is high time the Government should take a decision in the matter either nationalisation or tagging this unit with some big public sector undertaking like BHEL, because of such remarkable progress within a short period.

Under these circumstances, I urge upon the Government to task an early decision with regard to Motor and Machinery Manufacturers Ltd., Calcutta. I also demand that the Minister concerned make a statement in the House in this regard as early as possible stating the Government's decision.

(vii) PLIGHT OF BEEDI WORKERS OF SANTHAL PARGANAS, BIHAR

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : बिहार के अत्यन्त पिछड़ा जिला संथाल परगना में करीब चालीस हजार स्त्री-पुरुष और बालक बीड़ी बनाने के काम में लगे हैं। इनमें से 30 हजार देवघर अनुमंडल के हैं। ये सकड़ों गांवों में बिखरे हैं। इन मजदूरों का कोई